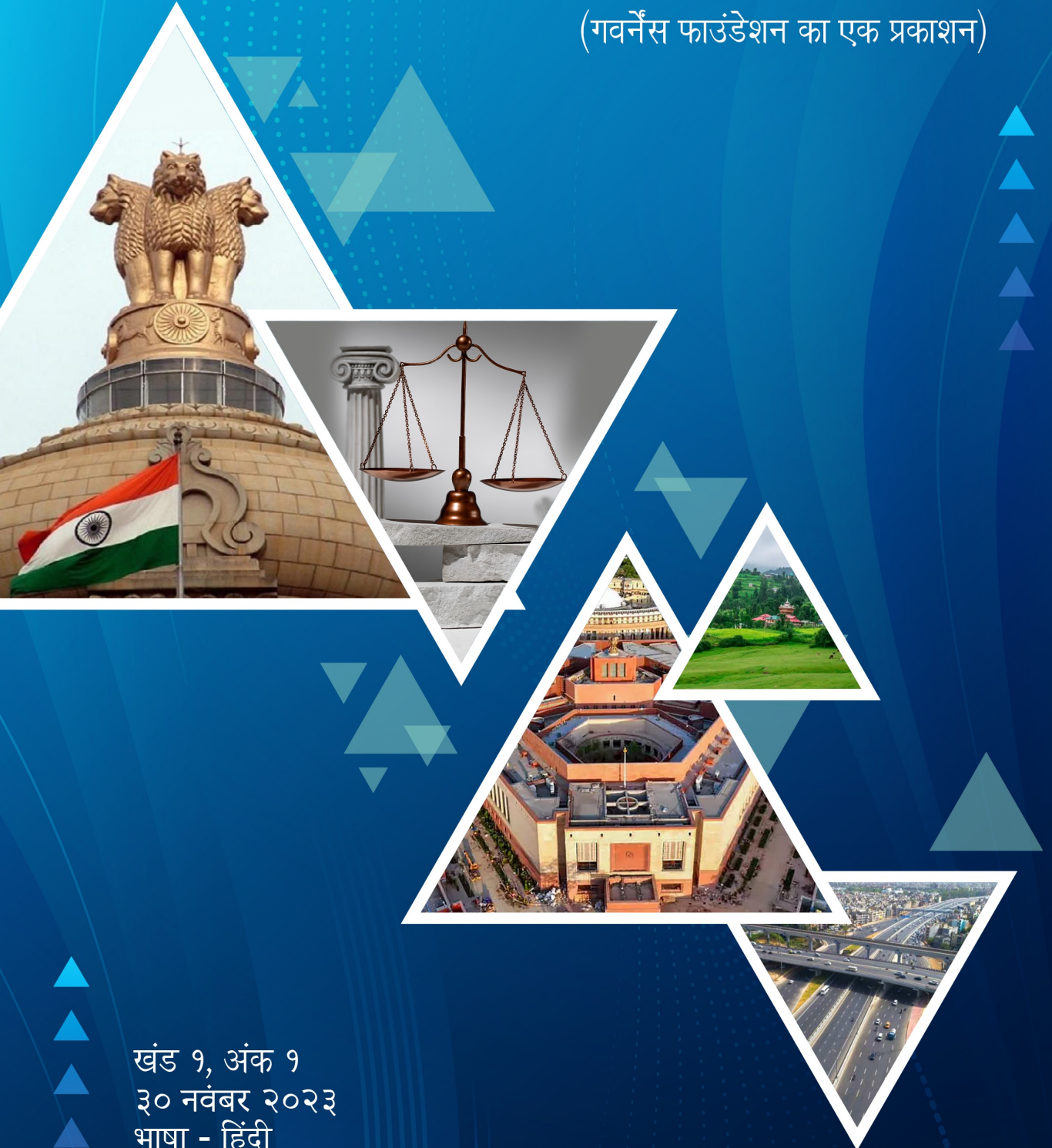




शासन दर्पण

(गवर्नेंस फाउंडेशन का एक प्रकाशन)



खंड १, अंक १
३० नवंबर २०२३
भाषा - हिंदी
कुल पृष्ठ - २६

गवर्नेंस फाउंडेशन की ओर से सुश्री सुमन मिश्रा द्वारा मुद्रित और प्रकाशित। स्वस्तिक क्रिएशन, 19, डीएसआईडीसी शेड, स्कीम III, ओखला फेज II, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट -110020 में मुद्रित और वी/18, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, लोअर ग्राउंड फ्लोर, नई दिल्ली -110016 में प्रकाशित।
संपादक: सिद्धार्थ मिश्रा

Printed and published by Smt. Suman Mishra on behalf of Governance Foundation. Printed at Swastika Creation, 19, DSIDC Shed, Scheme III, Okhla Phase II, Okhla Industrial Estate -110020 and published at V/18, Green Park Extension, Lower Ground Floor, New Delhi -110016. Editor: Siddharth Mishra

विषयसूची

01	शासन दर्पण के बारे में	4
02	पंचायती राज संस्थाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करना बेहतर एल्गोरिदम के माध्यम से सुशासन	5
03	लिंक सड़कों पर अतिक्रमण का मुद्दा और ग्रामीण भारत में चकरोड	8
04	सतर्कता प्रशासन को सुव्यवस्थित करना	14
05	मेघालय में नागरिक-केंद्रित शासन	16
06	उत्तराखंड की उभरती चुनौतियाँ - पुलिसिंग तंत्र में सुधार	18
07	अतीत से सबक	24

केस स्टडी 1: 1990 के दशक में बेंगलोर, भारत में सार्वजनिक सेवा वितरण पर रिपोर्ट कार्ड

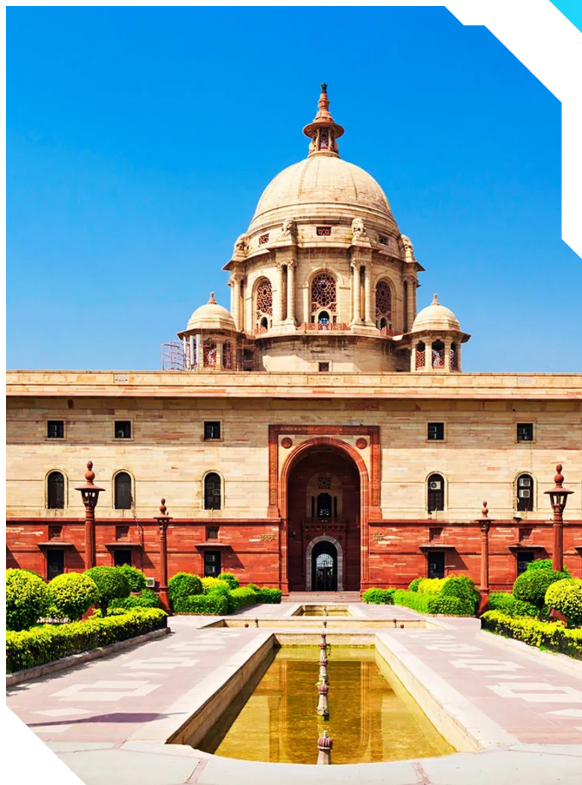
केस स्टडी 2: पुणे नगर निगम की सहभागी बजटिंग

शासन दर्पण के बारे में

- आर. पी. बत्रा, कार्यकारी निदेशक,
गवर्नेंस फाउंडेशन

2021 में स्थापित गवर्नेंस फाउंडेशन, बेहतर शासन प्रथाओं को बढ़ावा देकर और शासन में प्रमुख योगदानकर्ताओं पर ध्यान केंद्रित करके समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में काम करता है। जनता, मीडिया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। फाउंडेशन नवाचार और अनुसंधान को आगे बढ़ाने, जागरूकता फैलाने और क्षमता निर्माण, नीतियों और कार्यक्रमों पर वकालत, शासन ऑडिट आयोजित करने और सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के माध्यम से सेवाएं प्रदान करता है।

बेहतर शासन प्रथाओं को उजागर करने, समाज को परेशान करने वाले शासन संबंधी मुद्दों को संबोधित करने और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं पर जागरूकता फैलाने के लिए, फाउंडेशन अंग्रेजी भाषा में "गवर्नेंस मिरर" प्रकाशित करता है। प्रकाशन की सामग्री का एक मुख्य उद्देश्य रचनात्मक सामाजिक परिवर्तन लाना और न



केवल संरचनात्मक सुधार लाकर इसके निवारण की दिशा में काम करना है, बल्कि मानसिकता में बदलाव लाकर अपने उपभोक्ताओं को शासन सेवाओं की बेहतर डिलीवरी करना है। शासन दर्पण का यह उद्घाटन संस्करण लेखों और केस अध्ययनों की एक श्रृंखला के माध्यम से किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए प्रासंगिक सार्वजनिक सेवा वितरण, स्वास्थ्य और स्थिरता-आधारित विकास के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं पर प्रकाश डालता है। हम प्रासंगिक और पर्याप्त जानकारी देने और बेहतर प्रशासन प्रथाओं की दिशा में प्रयास करने के लिए आपकी तरह की प्रतिक्रिया और सुझावों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

पंचायती राज संस्थाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करना बेहतर एल्गोरिदम के माध्यम से सुशासन

- हर्ष श्रीवास्तव

भारत के गांवों, ब्लॉक पंचायतों, नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं और जिला पंचायतों में सैकड़ों हजारों पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) हैं। दशकों से, उन्होंने उम्मीदों के अनुरूप प्रदर्शन नहीं किया है और जैसा कि उनके मतदाता चाहते हैं, क्योंकि उनके पास सीमित धन, सीमित कार्य और कम सुसज्जित कार्यकर्ता हैं।

समीकरण के "कार्य" पक्ष को बढ़ाने के लिए संवैधानिक परिवर्तनों की आवश्यकता हो सकती है - संघ, समवर्ती और राज्य सूचियों के अलावा एक पीआरआई सूची जो उन क्षेत्रों की गारंटी देती है जिनके लिए पीआरआई जिम्मेदार हैं। इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की भी

आवश्यकता होगी ताकि राज्य सरकारें वैध रूप से कार्य (और उन कार्य के लिए प्रशासनिक अधिकार) को पीआरआई को हस्तांतरित कर सकें। उदाहरण के लिए, किसी भी बड़े शहर का अधिकांश बजट उस शहर के विकास प्राधिकरण द्वारा चलाया जाता है जो राज्य सरकार के प्रति जवाबदेह होता है, न कि नगर निगम द्वारा। इसलिए यह आलेख फ़ंक्शंस के बारे में बात नहीं करेगा।

धीरे-धीरे, पीआरआई को अधिक "धन" दिया जा रहा है। पहला, क्योंकि राज्य सरकार का राजस्व बढ़ रहा है, और इस प्रकार पीआरआई के पास अधिक पैसा आ रहा है। दूसरा, केंद्रीय वित्त आयोग और कुछ राज्य वित्त आयोग पीआरआई को कुल राजस्व का बढ़ता अनुपात आवंटित कर रहे हैं। पीआरआई के लिए अपने स्वयं के कर राजस्व को बढ़ाने की एक बड़ी और निरंतर समस्या है - वे कर लगाने के लिए नए स्रोत नहीं ढूँढ पाए हैं या कर दरों को बढ़ाने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं रखते हैं। उनके राजस्व व्यय भी बढ़ रहे हैं - वेतन, ईंधन इत्यादि, इसलिए सीवेज संयंत्रों और कचरा निपटान प्रणालियों जैसे पूंजीगत खर्चों के लिए भी कम उपलब्ध है। इस मुद्दे पर पर्याप्त विशेषज्ञों ने राय दी है, और यह फिर से इस मुद्दे से बेहतर ढंग से निपटने के लिए राज्य सरकार और पीआरआई निर्वाचित प्रतिनिधियों दोनों की राजनीतिक इच्छाशक्ति पर निर्भर करता है।

यह "कार्यकर्ता" को छोड़ देता है, जिस पर यह लेख ध्यान केंद्रित करेगा। पीआरआई को सौंपे गए अधिकांश सरकारी अधिकारी नियमित, पेंशनभोगी सरकारी कर्मचारी हैं। लेकिन कुछ मिलियन प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पीआरआई सदस्य भी हैं, जिनमें से एक तिहाई महिलाएं हैं। ये पीआरआई के वास्तविक पदाधिकारी हैं और इस लेख में तर्क दिया गया है कि यदि उनकी क्षमताओं को बढ़ाया जाता है, तो वे अपने संस्थानों को नेतृत्व प्रदान करने में सक्षम होंगे और इस प्रकार सीमित धन और कार्यों के साथ भी पीआरआई को बदल देंगे।

आईटी, कंप्यूटर-सहायता प्राप्त शिक्षण और यहां तक कि एआई का उपयोग करना ऐसे कुछ उपकरण हैं जिनका मैं प्रस्ताव करता हूँ जिन्हें पीआरआई की क्षमता बनाने के लिए सभी पीआरआई में आसानी से और व्यापक रूप से तैनात किया जा सकता है। आरंभ करने के लिए, सबसे मामूली ग्राम पंचायत के प्रत्येक नव-निर्वाचित पीआरआई सदस्य को अपनी भाषा में एक पंद्रह (या तीस) मिनट का वीडियो देखने में सक्षम होना चाहिए जिसमें उन्हें बताया जाए कि उनकी भूमिका क्या है, उनका अधिकार क्या है और उन्हें क्या संसाधन दिए जाएंगे। उन्हें जैसे कई हवाई जहाजों की आपातकालीन निकासी गाइड अगली सीट पर एक स्क्रीन पर एक वीडियो में दी जाती है, ये वीडियो ग्राफिक्स और एनिमेटेड पात्रों के साथ सरल भाषाओं में होंगे। जैसे विभिन्न प्रकार के विमानों के लिए अलग-अलग वीडियो हैं, वैसे ही पीआरआई के

प्रत्येक स्तर के लिए अलग-अलग वीडियो होंगे - एक ब्लॉक पंचायत सदस्य उनके लिए प्रासंगिक वीडियो देखेगा। ऐसे वीडियो प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा तैयार किए जाएंगे और पीआरआई कार्यालय में कंप्यूटर पर चलाए जाएंगे और प्रत्येक पीआरआई सदस्य के मोबाइल पर डाउनलोड के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। वे इस वीडियो को बाद में अपनी सुविधानुसार देख सकते हैं और जब भी वे इसका संदर्भ लेना चाहें तब देख सकते हैं।

परिचयात्मक वीडियो के अलावा, अन्य वीडियो भी होंगे- वार्षिक योजना और बजट कैसे तैयार करें; ग्राम सभाओं का संचालन कैसे करें; भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के सामान्य तरीके; कठिन कर्मचारियों को कैसे संभालें; पीआरआई की बैठकें कैसे आयोजित करें; राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं तक कैसे पहुंचें, आदि। इस तरह के पाठ्यक्रम एक साथ मिलकर प्रत्येक पीआरआई के लिए सभी भाषाओं और सभी स्तरों पर सीखने की एक खान अकादमी की तरह होंगे।

विशिष्ट कौशल और कार्यों पर वीडियो और ट्यूटोरियल के अलावा; पीआरआई सदस्य भी होने चाहिए उनके भावनात्मक भागफल और लचीलेपन को प्रबंधित करने, आत्म-प्रेरणा और दूसरों को प्रेरित करने जैसे नेतृत्व के नरम मुद्दों पर प्रशिक्षण (जहां संभव हो जूम के माध्यम से ऑनलाइन) प्रदान किया गया; विवाद प्रबंधन; समय प्रबंधन, आदि इसे उपयोग में आसान सॉफ्टवेयर प्रदान करके समर्थित किया जाएगा जो निर्वाचित पीआरआई सदस्यों को बजट, उपस्थिति, खरीदारी आदि जैसे दिन-प्रतिदिन (या त्रैमासिक या वार्षिक कार्यों) को संभालने में मदद करता है। यह सॉफ्टवेयर फिर से सभी प्रासंगिक भाषाओं में होना चाहिए और होना चाहिए जनजातीय क्षेत्रों के लिए अनुकूलित और स्वायत्त जिला परिषदें; शहरी क्षेत्रों के लिए; और सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए अलग से। सॉफ्टवेयर में ऐसे ग्राफ और चार्ट आने चाहिए जो आज तक के व्यय और बजटीय राशि में से कितना बचा है, यह दर्शाते हैं, ताकि पीआरआई सदस्यों के लिए यह ट्रैक करना आसान हो जाए कि उनका खर्च कहाँ हो रहा है।

पीआरआई सदस्य की सफलता को मापने के लिए इस सॉफ्टवेयर को समझने में आसान और उपयोग में आसान मापदंडों से जोड़ा जाना चाहिए। उसने कितनी बैठकों में भाग लिया है? वास्तविक व्यय बनाम बजटीय व्यय क्या है? क्या पीआरआई ने अपना धन जुटाने का लक्ष्य हासिल कर लिया? गवर्नर्स ऑडिट का समर्थन करने के लिए ऐसे पैरामीटर लचीले हो सकते हैं, जिसमें नव निर्वाचित पीआरआई सदस्यों को उनके लक्ष्यों के लिए "बाधा" दी जाती है।

इस सामान्य सॉफ्टवेयर समर्थन के अलावा, मैं पीआरआई को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की शक्ति का उपयोग करने का प्रस्ताव करता हूँ। सभी पीआरआई को कार्यों या कार्यों का एक सामान्य सेट पूरा करना होता है और अब हमारे पास खर्च, बजट, मरम्मत, भर्ती, खरीद पर दशकों का डेटा है। यदि यह डेटा एआई इंजन में डाला जाता है, तो इंजन पीआरआई नेताओं को सिफारिशें भी कर सकता है क्योंकि वे अपने सॉफ्टवेयर का उपयोग करना शुरू करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड सॉफ्टवेयर आपके टाइप करते ही शब्दों की भविष्यवाणी करने में सक्षम है (जैसा कि जीमेल करता है)। चैट जीपीटी (माइक्रोसॉफ्ट द्वारा खरीदा गया) और बार्ड (गूगल द्वारा) पहले से ही प्रश्नों का उत्तर देना आसान बनाने के लिए शक्तिशाली एआई उपकरण विकसित कर रहे हैं। हमें अपनी खुद की पीआरआई के लिए बनी सहायता प्रणाली बनाने के लिए ऐसे उपकरणों का उपयोग करना चाहिए।

इसलिए, यदि मासिक बजट बनाना है, तो एआई प्रभारी पीआरआई सदस्य को यह कहते हुए एक सिफारिश दे सकता है कि स्वास्थ्य बनाम शिक्षा के लिए सबसे अच्छा आवंटन 40:60 होगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि यह 80 प्रतिशत में काम करता है। मामलों का। या यदि पीआरआई सदस्य को लग रहा है कि कर्मचारियों की उपस्थिति कम हो गई है; तब एआई इंजन यह सुझाव दे सकता है कि 71 प्रतिशत मामलों में जो उपाय सबसे अच्छा काम करता था, वह था डिफॉल्ट करने वाले कर्मचारियों को चेतावनी पत्र जारी करने के बजाय उनका नाम लेना और उन्हें शर्मिंदा करना।

चूंकि अधिक से अधिक डेटा सभी पीआरआई में चल रहे एक ही सॉफ्टवेयर द्वारा कैप्चर किया जाता है, यह अधिक से अधिक भाषाओं में अधिक से अधिक स्थितियों के लिए बेहतर और बेहतर सिफारिशें करने में सक्षम होगा। बाद में एआई अनुशंसा को ध्वनि-सक्षम किया जा सकता है, इसलिए पीआरआई सदस्य को केवल अपने मोबाइल फोन (या कंप्यूटर) में अपनी चिंता व्यक्त करनी होगी और अनुशंसा प्राप्त करनी होगी।



वीडियो ट्यूटोरियल, उपयोग में आसान सॉफ्टवेयर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस संयोजन से निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमताओं और क्षमताओं में वृद्धि होनी चाहिए। और जो लोग साक्षर या संख्यात्मक नहीं हैं, उनके लिए बुनियादी, मूलभूत, कैच-अप कक्षाएं हो सकती हैं जिन्हें वे ले सकते हैं और इस प्रकार अपने गांव, ब्लॉक के पदाधिकारियों, निधियों और कार्यों के प्रबंधन के लिए जल्दी से तैयार हो सकते हैं। जिला, या शहर. यह सब विकसित करना महंगा नहीं होगा, इसका कुछ हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा विकसित किया जा सकता है, और बाकी राज्य सरकारों द्वारा सामान्य राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुसार किया जा सकता है। प्रत्येक राज्य सरकार के पास वीडियो निर्माताओं और ऐप डेवलपर्स के अलावा, अपने राज्य में पीआरआई के लिए कम्प्यूटरीकरण, सीखने और विकास और एआई समर्थन का प्रबंधन करने के लिए एक अलग इकाई होनी चाहिए। ऐसी इकाई को समाजशास्त्रियों, मानवविज्ञानियों, भाषाविदों, ग्राफिक डिजाइनरों और जहां संभव हो, उन लोगों को नियुक्त करना चाहिए जो पहले पीआरआई नेता चुने गए हैं। सबसे उपयोगकर्ता-अनुकूल ट्यूटोरियल वीडियो तैयार करने और एआई इंजन द्वारा उपयोग किए जाने वाले डेटा और एल्गोरिदम को क्यूरेट करने के लिए ऐसे विविध समूह की आवश्यकता है। केंद्र सरकार को ऐसी संस्थाओं को वित्त पोषित करना चाहिए, जो अपनी सेवाओं के लिए प्रत्येक पीआरआई से एक छोटा लाइसेंस शुल्क भी ले सकते हैं।

मेरा मानना है कि परदे के पीछे का यह हस्तक्षेप और समर्थन, सबसे उपयोगी और लागत प्रभावी हस्तक्षेप है जो सभी पीआरआई के प्रशासन और कार्यप्रणाली में तुरंत सुधार लाने और इस प्रकार सभी को बेहतर प्रशासन प्रदान करने के लिए किया जा सकता है।

लिंक सड़कों पर अतिक्रमण का मुद्दा और ग्रामीण भारत में चकरोड

- अन्नपूर्णा

परिचय

लिंक सड़कें या चकरोड, जैसा कि इन्हें आमतौर पर कहा जाता है, किसानों को कृषि उपज और कृषि सामग्री जैसे मशीनरी, उर्वरक आदि को कृषि भूमि से कृषि भूमि तक पहुंचाने के लिए मुख्य सड़कों तक आसान पहुंच प्रदान करती है। देश के कई हिस्सों में इन सड़कों को संदर्भित करने के लिए कृषि सड़कें, कृषि सड़कें और इसी तरह के शब्दों का भी उपयोग किया जाता है। अध्ययनों और हस्तक्षेपों ने स्थापित किया है कि लिंक सड़कों का कृषि उपयोग, प्रत्येक वर्ष किसान द्वारा की जाने वाली फसलों की संख्या, खेती का समय, कृषि उपज की मात्रा, फसल का प्रकार, श्रमबल की उपलब्धता, मशीनरी की पहुंच पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। और उपकरण, आदि लिंक सड़कों (कृषि सड़कें, कृषि सड़कें आदि) पर अतिक्रमण, सामान्य भूमि, विशेषकर चकरोडों पर अवैध कब्जा और खेती पूरे देश में बहुत बड़े पैमाने पर है। इससे किसानों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के साथ-साथ कृषि उपज और अन्य सामान को खेतों तक लाने-ले जाने वाले अन्य हितधारकों के लिए बड़ी चुनौतियाँ और असुविधाएँ पैदा होती हैं।

लगभग सभी प्रकार की ग्रामीण सड़कों - कृषि सड़कें, लिंक सड़कें, कृषि सड़कें इत्यादि पर अत्यधिक सड़क अतिक्रमण के कारण कई मामलों में लिंक सड़कों की चौड़ाई कम हो गई है। वर्तमान स्थिति के तहत, इसका आकलन करना काफी आवश्यक है मौजूदा लिंक सड़कों पर अतिक्रमण की आर्थिक लागत और इस लापरवाह, लेकिन बहुत गंभीर समस्या के कारण कृषि क्षेत्र को होने वाले सकल घरेलू उत्पाद में नुकसान और देश भर में लिंक सड़कों से अतिक्रमण हटाने के उपाय खोजने का प्रयास करें ताकि इसका लाभ उठाया जा सके। इन सड़कों को पहले स्थान पर रखने का लाभ। यह स्थापित किया गया है कि ग्रामीण सड़कों का सुधार ग्रामीण लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाता है और यही बात कृषि सड़कों के लिए भी सच है। इस संबंध में, अब समय आ गया है कि कृषि सड़क अतिक्रमण के मुद्दे को एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में संबोधित किया जाए, और जागरूकता, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, चर्चा, डिजिटल के उपयोग जैसे विभिन्न उपायों के माध्यम से समस्या के व्यापक शमन की दिशा में निश्चित कदम उठाए जाएं। उपकरण, लिंक सड़कों/फार्म सड़कों का डिजिटल सीमांकन और भू-स्थानिक डेटाबेस का विकास, और प्रवर्तन, आदि।



पृष्ठभूमि

शिक्षा, स्वास्थ्य, विपणन आदि जैसी सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करके ग्रामीण कनेक्टिविटी ग्रामीण लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण घटक बन जाती है। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था अभी भी कृषि आय पर बहुत अधिक निर्भर है और इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि कृषि में बाधा डालने वाले मामले इस क्षेत्र को गंभीरता से देखा जाता है और उचित महत्व और तात्कालिकता के साथ संबोधित किया जाता है। यह स्थापित किया गया है कि ग्रामीण सड़कों में निवेश ग्रामीण लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाता है और कृषि सड़कों/लिंक सड़कों के मामले में भी यही स्थिति है, जिसमें उन किसानों के उत्थान की क्षमता है जो अपनी आय के एकमात्र साधन के रूप में सीधे कृषि उपज पर निर्भर हैं। . साक्ष्य यह भी इंगित करते हैं कि जैसे-जैसे ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार होता है, ग्रामीण गरीबी का स्तर कम हो जाता है।

भूमि पर बढ़ते दबाव के कारण आम भूमि पर अतिक्रमण, अवैध कब्जा और खेती लगभग पूरे भारत में होती है और कई अन्य देशों में भी यह एक समस्या है। इनमें से अधिकांश अतिक्रमण आम और निजी भूमि की सीमाओं पर हुआ है। ज़मीन के मालिक, ज्यादातर मामलों में स्वयं किसान, जिनके पास आम ज़मीन से सटी हुई निजी ज़मीन होती है, धीरे-धीरे सीमा चिन्ह को हटाकर अतिक्रमण करते हैं, आम ज़मीन को अपनी जोत में शामिल कर लेते हैं, और दूसरों को छोड़कर उस पर अपनी ज़मीन के रूप में खेती करते हैं। पूरे देश में राजस्व विभागों के लिए गांव से खेत तक की सड़कें एक दुर्लभ लेकिन जटिल समस्या हैं। सड़कें कभी-कभी पीढ़ियों तक अतिक्रमणित रहती हैं, क्योंकि अधिकांश अतिक्रमणकारी बड़े जमींदार या राजनीतिक रूप से अच्छी तरह से जुड़े हुए किसान होते हैं जो अतिक्रमण विरोधी अभियान को पटरी से उतारने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करते हैं। अधिकारी, और यहां तक कि अन्य ग्रामीण भी, विभिन्न महंगी प्रवर्तन तकनीकों के माध्यम से इस तरह के अतिक्रमण को रोकने का प्रयास करते हैं, फिर भी कुछ अतिक्रमण अनिवार्य रूप से पता नहीं चल पाता है या दंडित नहीं हो पाता है। अक्सर इस अतिक्रमण के बाद वर्षों बाद अतिक्रमणकर्ता को पूर्व पद पर स्थायी और हस्तांतरणीय संपत्ति के अधिकार दिए जाते हैं, एक प्रक्रिया जिसे भारत में नियमितकरण के रूप में जाना जाता है, प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से अधिकारों का औपचारिककरण।



भारत में भूमि अतिक्रमण कानून और दंड

भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 441, भारत में संपत्ति और भूमि अतिक्रमण से संबंधित है। इस धारा के अनुसार अतिक्रमण तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य की भूमि या संपत्ति में अवैध रूप से प्रवेश करने का प्रयास करता है।

आईपीसी की धारा 441 निजी संपत्ति में अतिक्रमण पर भी लागू होती है। धारा 442 के अनुसार इसे अपराध माना जाता है। इसके अलावा अधिनियम के अनुसार, न्यायपालिका अतिक्रमणकारियों को किसी और की संपत्ति का उल्लंघन करने से रोक सकती है या रोक सकती है।

न्यायपालिका अतिक्रमणकर्ता को किसी अन्य की संपत्ति का उल्लंघन करने के लिए मुआवजा देने के लिए भी कह सकती है। मुआवजे का मूल्यांकन अतिक्रमण से हुए नुकसान और जमीन की मौजूदा कीमत के आधार पर किया जाता है। आदेश 39 के अनुसार भूमि मालिक अदालत में जाकर नुकसान का दावा कर सकता है।

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 की धारा 441 भूमि और संपत्ति अतिक्रमण पर लागू होती है। यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है, तो उन्हें 550 रुपये का जुर्माना और तीन महीने तक की कैद होगी।



लिंक रोड अतिक्रमण के प्रकार और स्रोत

- सामान्य भूमि पर अवैध कब्ज़ा एवं खेती
- लिंक सड़कों के माध्यम से अवैध खुदाई और जल निकासी और/या जल चैनल स्थापित करना
- सड़क की भूमि पर या उसके ऊपर लटकती हुई किसी इमारत या किसी अन्य संरचना जैसे कि दीवारें, चारदीवारी, बालकनियाँ, बरामदे, छज्जा प्रक्षेपण का निर्माण
- निर्धारित अवधि से परे, यदि कोई हो, निर्माण सामग्री या किसी अन्य प्रकार के सामान का ढेर लगाकर, बिक्री के लिए वस्तुओं का प्रदर्शन करके, खंभे, शामियाना, तंबू, पंडाल और अन्य समान निर्माण करके या वाहनों को पार्क करके या घरेलू अस्तबल बनाकर कब्ज़ा करना। जानवरों के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए
- किसी भी सड़क की भूमि पर किसी भी प्रकार की खुदाई या तटबंध बनाया या बढ़ाया गया हो
- सड़क अतिक्रमण से किसानों को हो रही परेशानी
- खेती की सामग्री, मशीनरी, उर्वरक आदि को खेतों तक पहुंचाने में असमर्थता
- बैलगाड़ी, ट्रैक्टर के लिए सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण अधिकांश किसानों को खाद, बीज और उपकरण सिर पर लादकर खेतों तक ले जाना पड़ता है।
- सड़कों की कमी के कारण किसानों को उपज के परिवहन के लिए अन्य खेतों का उपयोग करना पड़ता है और तब तक इंतजार करना पड़ता है जब तक पड़ोसी खेतों से खड़ी फसलें खाली नहीं हो जातीं।
- सड़कों के किनारे अतिक्रमणकारियों द्वारा बनाये गये ऊंचे-ऊंचे बांधों के कारण बारिश के पानी से सड़कें टूट जाती हैं
- बारिश के मौसम में बारिश के पानी से क्षतिग्रस्त सड़कें उपयोग के लायक नहीं रहती हैं और कई महीनों तक खेत तक आने-जाने के लिए कोई भी परिवहन संभव नहीं होता है, जिसके परिणामस्वरूप फसल काटने में देरी होती है, फसलों का नुकसान होता है, चरम बाजार कीमतों तक पहुंच का नुकसान होता है, आदि।
- किसानों के बीच लंबे समय से चल रहा भूमि विवाद
- मजदूरों की लंबी यात्रा करने की अनिच्छा
- खेतों तक पहुँचने के लिए पैदल दूरी तय करनी पड़ती है
- पसंदीदा फसलों, नकदी तक पहुंच का नुकसान
- औजारों, मशीनरी आदि की अनुपलब्धता के कारण फसलें।



अतिक्रमण से निपटने के लिए मुख्य रणनीतियाँ

- जीआईएस आर्किटेक्चर एक आवश्यक उपकरण है जिसे किसी स्थान और समय पर स्थानिक और गैर-स्थानिक डेटा की जानकारी को समझने के लिए रखा जाना चाहिए। ग्रामीण कृषि सड़क नेटवर्क में नोड्स और लिंक का एक समूह शामिल है। नेटवर्क कॉन्फिगरेशन इन लिंक्स का एक संयोजन है जो नोड्स के लिए एक दिशात्मक अभिविन्यास के साथ है जो अंतरिक्ष में फैली बस्तियों के केंद्र प्रमुख हैं। चूंकि अधिकांश विशेषताएं प्रकृति में स्थिर हैं, इसलिए स्थायी रूप से जियो-रेफरेंस की आवश्यकता होती है और योजना, निर्माण, रखरखाव के संदर्भ में गतिशील इंटरैक्शन को इस स्थानिक फ्रेम पर एक समय में देखा जा सकता है। ग्रामीण संपत्ति बनाने के लिए, जीआईएस एक महान सहायक उपकरण है जो उन्नत प्रौद्योगिकियों और पारंपरिक प्रथाओं को एक आम मंच पर जोड़ता है
- देश में सभी लिंक सड़कों, कृषि सड़कों, कृषि सड़कों का भू-स्थानिक सर्वेक्षण करें और अतिक्रमणों की पहचान करें और सड़क नेटवर्क, अतिक्रमित क्षेत्रों आदि का एक डिजिटल ज्ञान बैंक बनाएं।
- लिंक सड़कों के अतिक्रमण से जुड़े प्रभावों पर नगर पालिकाओं और अन्य राज्य एजेंसियों की शिक्षा और प्रशिक्षण बढ़ाएँ
- भूमि उपयोग प्राधिकरणों, संबंधित सरकारी एजेंसियों, नगर पालिकाओं, ग्राम निकायों आदि के साथ तकनीकी रूप से सहायता और कार्यक्रमों का समर्थन करने की क्षमता विकसित करना और बनाए रखना।
- सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर ऐसी सभी सड़कों पर जिला स्तरीय अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू करें, मुद्रित सामग्री, फोटो लाइब्रेरी सहित एक मल्टीमीडिया शैक्षिक कार्यक्रम बनाएं, वीडियो, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन और फ़िल्ड प्रदर्शन, जो अतिक्रमण के प्रभावों और शमन रणनीतियों पर चर्चा करते हैं
- विभिन्न प्रकार के तनावों पर दीर्घकालिक लिंक रोड निगरानी करना जारी रखें और भू-स्थानिक तकनीकी प्रगति के साथ निगरानी रणनीतियों को अद्यतन करें।
- आगे के अतिक्रमणों को रोकने के तरीके के रूप में स्वयंसेवी निगरानी प्रयासों को एकीकृत करें
- पुनः अतिक्रमण को रोकने के लिए सड़क किनारे खाइयों के किनारे पेड़ों की कतारें बनाने जैसी नवीन रणनीतियां पेश करें।
- डिजिटल डेटाबेस की निरंतर निगरानी और अद्यतनीकरण
- मजबूत प्रवर्तन उपाय और कड़े अतिक्रमण जुर्माने की शुरुआत
- खेत की सड़कों के लिए ग्राम स्तरीय व्यवस्थित रखरखाव टास्क फोर्स की शुरुआत



सड़क से अनुमानित परिणाम अतिक्रमण हटाना

- किसानों के लिए कृषि मशीनों, उर्वरकों को खेतों तक पहुंचाना आसान हो गया है
- किसानों के लिए अपने कृषि उत्पादों को बैलगाड़ी और यहां तक कि ट्रैक्टरों पर मंडियों/हाटों तक ले जाना आसान हो गया है।
- साल भर कृषि भूमि तक पहुंच, यहां तक कि मानसून के मौसम के दौरान भी
- भूमि मूल्य में सुधार
- बढ़ी हुई पहुंच का अर्थ है उन्नति रोजगार के अवसरों की
- स्थानीय परिवहन की बढ़ती उपलब्धता के कारण, परिवहन में समय कम लगता है और कम चुनौतीपूर्ण
- भूमि विवाद में कमी, कानून में सुधार और आदेश की स्थिति
- सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय एकता प्राप्त करना, और आर्थिक उत्थान और समावेशी विकास ग्रामीण कनेक्टिविटी के माध्यम से
- कृषि भूमि उपयोग, निवेश में वृद्धि लाभदायक फसलों और भाड़े के श्रम में
- अतिक्रमण मुक्त कनेक्टिविटी कृषि से परे स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे परिणामों में सुधार करती है और ग्रामीण समुदायों के लिए परिवर्तनकारी सकारात्मक बदलाव लाती है। कृषि से राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में सुधार क्षेत्र
- आधुनिक खेती शुरू करने का अवसर ग्रामीण खेती में विधियाँ और प्रौद्योगिकी-सहायता प्राप्त, मशीनरी सहायता प्राप्त विधियाँ



सतर्कता प्रशासन को सुव्यवस्थित करना

- आर. पी. बत्रा, कार्यकारी निदेशक, गवर्नेंस फाउंडेशन

यह माना जाता है कि भ्रष्टाचार के प्रमुख कारण हैं

- I. प्रशासनिक देरी
- II. सरकार नियामक कार्यों के माध्यम से जितना प्रबंधन कर सकती है उससे अधिक अपने ऊपर लेना
- III. विभिन्न श्रेणियों में निहित शक्तियों के प्रयोग में व्यक्तिगत विवेक की गुंजाइश सरकारी कर्मचारी
- IV. और विभिन्न मामलों से निपटने की बोझिल प्रक्रियाएँ जो नागरिकों के लिए उनके दैनिक मामलों में महत्वपूर्ण हैं।

नैतिकता और शासन में, जवाबदेही का अर्थ है भूमिका या रोजगार की स्थिति के दायरे में कार्यों, निर्णयों और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी की स्वीकृति और धारणा और परिणामी परिणामों के लिए रिपोर्ट करने, समझाने और जवाबदेह होने के दायित्व को शामिल करना।

"कानून के शासन" की विशेषता पूर्व अपेक्षित "निष्पक्ष कानूनी ढांचे" के रूप में निहित है जिसे निष्पक्ष रूप से लागू किया जाता है। इसका अर्थ स्वतंत्र न्यायपालिका और एक निष्पक्ष एवं निष्कलंक पुलिस बल भी है। संवैधानिक प्रावधानों के अलावा, कुछ नियम हैं जो दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की कार्यवाही के संचालन पर लागू होते हैं। केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1965 केंद्र सरकार के अधिकांश कर्मचारियों को कवर करते हैं। इसके अलावा, कई अन्य नियम भी हैं जो विभिन्न वर्गों पर लागू होते हैं कई सेवाओं में कर्मचारी। हालाँकि सीसीएस (सीसीए) नियम 1965 केवल सरकार में सीमित संख्या में कर्मचारियों पर लागू होते हैं, अनिवार्य रूप से ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का संहिताकरण हैं, जिनका किसी भी अर्ध न्यायिक कार्यवाही में पालन किया जाना आवश्यक है। यहां तक कि संविधान के भाग XIV में निहित संवैधानिक सुरक्षाएं भी उपरोक्त सिद्धांतों का संहिताकरण हैं। इसलिए, अधिकांश सरकारी और अर्ध-सरकारी संगठनों में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएँ कमोबेश समान हैं। लेकिन जुर्माना लगाने का अधिकार अपने साथ न्यायपूर्ण कार्य करने का कर्तव्य भी रखता है।

इस संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सीएजी लेखापरीक्षा/निरीक्षण की स्थापित प्रथा और दिशानिर्देशों के अनुसार, संबंधित इकाई की लेखापरीक्षा रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले, सभी लेखापरीक्षा निष्कर्षों, निष्कर्षों और सिफारिशों पर संबंधित इकाई के प्रमुख के साथ चर्चा की जाती है और जहां तक संभव हो लेखापरीक्षित इकाई की सीधी प्रतिक्रियाएं होती हैं। एक बैठक में अनुरोध किया जाना चाहिए और रिकॉर्ड किया जाना चाहिए जिसे "एग्जिट कॉन्फ्रेंस" या "एग्जिट इंटरव्यू" भी कहा जाता है। यह जहां तक संभव हो ऑडिट निष्कर्षों और सिफारिशों के बारे में एक ऑडिट इकाई के साथ समझौते पर पहुंचने का एक मंच है।

निकास साक्षात्कार के समय सीवीओ को शामिल करने से सतर्कता शाखा और सी एंड एजी निरीक्षण/ऑडिट परिणाम के बीच सीधा संबंध मिल सकता है और सतर्कता विभाग द्वारा मामले की सतर्कता जांच शीघ्र शुरू हो सकती है।

यह मुद्दा आयोग द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सचिव व्यय और सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग के साथ उठाया गया था। इस प्रणाली को संस्थागत बनाने की दिशा में पहले कदम के रूप में, आयोग ने कुछ सार्वजनिक उपक्रमों को पायलट आधार पर सीएजी ऑडिट निरीक्षण टीम द्वारा निकास साक्षात्कार के समय सीवीओ को शामिल करने की प्रथा अपनाने की सलाह दी है।

यह देखा गया है कि राजनीतिक दबाव के कारण सरकारी सेवकों के विरुद्ध अभिकल्पित आरोप लगाये जा रहे हैं। वास्तविक कार्य और निर्णय सोशल-मीडिया और राजनीतिक दलों की जांच के अधीन हैं। रातों-रात बेदाग सेवा रिकॉर्ड वाले अधिकारी खलनायक बन जाते हैं। अधीनस्थों और सहकर्मियों के विचारों को शायद ही कभी ध्यान में रखा जाता है। इस प्रकार परिणामी कम सम्मान वाले एक ईमानदार अधिकारी को उचित अवसर दिए बिना आरोप पत्र दायर किया गया, बलि का बकरा बना दिया गया। यद्यपि अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करते समय उचित प्रक्रिया का पालन किया जाता है, लेकिन उचित अवसर के तत्व को नजरअंदाज कर दिया जाता है। एक तरह से कर्मचारी की ईमानदारी को चुनौती दी गई है। हालाँकि, कुछ परिस्थितियों में और पीड़ित अधिकारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए मानव संसाधन विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए, निम्नलिखित की अनुशंसा की जाती है:

1. 360 डिग्री मूल्यांकन: पीड़ित अधिकारी के "प्रदर्शन की समीक्षा" करना। केवल प्रत्यक्ष पर्यवेक्षक के बजाय सहकर्मियों और अधीनस्थों से प्रतिक्रिया प्राप्त करें। 360 डिग्री प्रक्रिया अलग है, इसमें यह। यह प्रक्रिया संगठन को यह बेहतर ढंग से समझने में सक्षम बनाती है कि कर्मचारी ने टीम के हिस्से के रूप में कैसे और किन परिस्थितियों में कार्य किया है। इस जानकारी पर बाद में आगे की पूछताछ के दौरान विचार किया जाना है;
2. सारांश सुनवाई: प्रारंभिक जांच के बाद विभागीय स्तर पर व्यक्ति की बात सुनी जानी चाहिए;
3. प्रारंभिक जांच: इसकी रिपोर्ट के आधार पर, एक "तथ्य पत्र" समयबद्ध तरीके से तैयार किया जा सकता है, जैसे कि 3 महीने के भीतर;
4. खुला दरबार प्रणाली: वरिष्ठ स्तर पर, आरोपी सरकारी कर्मचारियों तक "सीधी पहुंच" प्रदान करने के लिए; पीड़ित अधिकारी को सार्वजनिक सुनवाई के माध्यम से वरिष्ठ स्तर तक पहुंच प्राप्त होनी चाहिए; और
5. कोई नियमित अभियोजन नहीं: विभागीय स्तर पर गंभीर मामलों में कोई नियमित अभियोजन नहीं बल्कि केवल अर्ध-न्यायिक जांच होनी चाहिए। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में किसी भी देरी को कर्तव्य में लापरवाही माना जाना चाहिए; और
6. मुफ्त कानूनी सहायता: विभाग को किसी अधिकारी के सद्भावनापूर्ण कार्यों का समर्थन करने और उसका मनोबल बढ़ाने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करनी चाहिए।



मेघालय में नागरिक-केंद्रित शासन

- वासिन्द्र मिश्र

मेघालय अपने नागरिक केंद्रित शासन मॉडल के लिए देश की अग्रणी सरकारों में से एक हो सकता है। कॉनराड संगमा की सरकार वास्तव में "अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार" के दर्शन के अनुसार राज्य मशीनरी को तैयार करने की कोशिश कर रही है। 2020 में मेघालय सरकार ने एक अधिनियम बनाया था - "मेघालय लोक सेवा का अधिकार अधिनियम 2020" इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार के सभी संबंधित विभाग नागरिकों के हित में कार्य करने और कार्य करने के लिए बाध्य हैं।

मेघालय लोक सेवा अधिकार अधिनियम 2020 के तहत 100 से अधिक सेवाएं शामिल हैं। मेघालय राज्य विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाले हैं और सरकार के वर्तमान गठबंधन सहयोगी अपने प्रदर्शन के आधार पर जनादेश पाने के लिए आश्वस्त हैं। लॉन्च के दौरान बोलते हुए, संगमा ने कहा कि राज्य प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय कर रहा है कि हर विभाग में नागरिक केंद्रित शासन लागू किया जा रहा है।

"कई बार कुशलतापूर्वक और तेजी से वितरण करने की मूल अवधारणा से ध्यान भटक जाता है क्योंकि अधिकांश समय लक्ष्य प्राप्त करने और योजनाओं को लागू करने, दिशानिर्देशों का पालन करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है।"

नियम यह है कि हम भूल जाते हैं कि हम यहां लोगों की सेवा करने के लिए हैं, "उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि एकीकृत वेब पोर्टल नागरिक-केंद्रित शासन प्राप्त करने और समग्र वितरण तंत्र में सुधार की दिशा में एक कदम है। "सभी 188 सेवाओं को जल्द से जल्द पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए," - उन्होंने उल्लेख किया और सभी स्तरों पर विभागों से समयसीमा का पालन करने का आग्रह किया ताकि कोई देरी न हो।

यह ध्यान देने योग्य है कि 'मेघालय लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2020' निर्धारित समय सीमा के भीतर नागरिकों को अधिसूचित सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी की देखभाल करने के लिए एक अधिनियम है, जिसमें डिफॉल्ट के मामले में सरकारी सेवाओं की देनदारियां भी शामिल हैं। यह पोर्टल नागरिकों को अधिकतम सुविधा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह एक एकीकृत वेब पोर्टल और अधिकारियों और आयोग के लिए एक डैशबोर्ड है जो प्रत्येक चरण में सभी आवेदनों की स्थिति की निगरानी करने में सक्षम बनाता है।

एक आधिकारिक बयान में बताया गया, "खराब नेटवर्क कनेक्टिविटी वाला नागरिक सामान्य सेवा केंद्रों में पोर्टल की सेवाओं का लाभ उठा सकता है।"

नागरिक केंद्रित शासन प्राप्त करने की दिशा में यह एक क्रांतिकारी कदम है और सरकार सरकारी विभागों द्वारा नागरिकों को सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी के प्रावधान के माध्यम से जो हासिल करने की कोशिश कर रही है, उसके मूल में है। मेघालय सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है कि कई ई-गवर्नेंस पहल सीधे नागरिकों के दरवाजे तक पहुंचें, जिससे ये सेवाएं सभी के लिए सुलभ हो जाएं, यहां तक कि दूरदराज के स्थानों पर रहने वाले लोगों के लिए भी।

जनता के सामने आने वाली बाधाओं को ध्यान में रखते हुए, मेघालय के मुख्यमंत्री - कॉनराड संगमा ने 5 ऑनलाइन सेवाएं भी शुरू की हैं - विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री की सामाजिक सहायता योजना; राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन नागरिक-केंद्रित सेवा; राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली (एनजीडीआरएस); एमटीसी बस सेवाओं के लिए ई-टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग; वार्षिक संपत्ति रिटर्न ऑनलाइन जमा करना।



इसके अलावा, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के तहत राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन नागरिक-केंद्रित सेवा - राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली (आरसीएमएस) डिजिटल रूप से सक्षम पीडीएस का एक हिस्सा है, जो नागरिकों को परिवार के विवरण, आधार सीडिंग, स्थानांतरण/सरेडर को संशोधित करने की अनुमति देती है। राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली (एनजीडीआरएस) - राजस्व विभाग के तहत एक पहल, नागरिकों को साक्ष्य के संरक्षण, स्वामित्व के आश्वासन, दस्तावेजों के प्रचार और धोखाधड़ी की रोकथाम के उद्देश्य से, पंजीकरण प्राधिकरण के साथ भूमि दस्तावेजों को पंजीकृत करने में सक्षम बनाएगी।

इस बीच, एमटीसी बस सेवाओं के लिए ई-टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग - परिवहन विभाग की एक पहल संभावित पर्यटकों और यात्रियों को शेड्यूल और मार्गों तक पहुंच प्रदान करेगी, ई-टिकट बुक करेगी, ऑनलाइन भुगतान करेगी और यात्रियों को अपडेट करती रहेगी। एसएमएस/ईमेल अलर्ट.

वार्षिक संपत्ति रिटर्न की ऑनलाइन प्रस्तुति - कार्मिक एवं ए.आर. के तहत। विभाग निम्नलिखित संवर्ग एमसीएस, एमपीएस, एमएफएस, एमएसएस आदि के सरकारी कर्मचारियों के लिए है। यह कर्मचारियों को चल और अचल संपत्ति रिटर्न दोनों ऑनलाइन दाखिल करने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री ने स्कूलों, पुलिस स्टेशनों और स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाओं में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए भी कहा है।

1800 सरकारी एलपी स्कूलों की मरम्मत और नवीनीकरण विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण से किया जाएगा, जहां जिला स्तरीय समिति और शिक्षा अधिकारियों के साथ डीआरडीए यह सुनिश्चित करेगा कि इन स्कूलों में सुधार और नवीनीकरण कार्य किए जाएं, जिसमें पानी की आपूर्ति, बिजली और फर्नीचर भी शामिल होंगे। सुधार के समान मॉडल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और पुलिस स्टेशनों के लिए भी अपनाए गए।

“इस प्रकार के मरम्मत कार्यों को सरकार के विभिन्न विभागों से गुजरना पड़ता था, जिसके कारण विभिन्न नवीकरण कार्यों में बहुत देरी होती थी, इसलिए अब जिले विकेंद्रीकृत तरीके से जिला स्तर पर मरम्मत कार्यों को करेंगे, जिससे तेजी से मरम्मत सुनिश्चित होगी। काम करता है,” उन्होंने आगे कहा।

इस बीच, राज्य प्रशासन द्वारा परिकल्पित 'पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर रेनोवेशन फंड' भी शुरू किया गया है। निर्णय लिया गया कि राज्य भर के 76 पुलिस स्टेशनों को नए वाहन मिलेंगे। उन्होंने कहा, “पुलिस स्टेशन न केवल कानून और व्यवस्था लागू करने का कर्तव्य निभाते हैं बल्कि वे जनता के लिए संपर्क का पहला बिंदु भी हैं और आपात स्थिति के समय अतिरिक्त गतिविधियों में भी शामिल होते हैं।” उन्होंने टिप्पणी की कि सभी पुलिस स्टेशनों को कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेट-अप के साथ मजबूत किया जाएगा और उच्च यातायात क्षेत्रों और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में क्रेन और एम्बुलेंस दी जाएंगी। यातायात को नियंत्रित करने और यातायात गतिविधियों की निगरानी करने के लिए, विशेष रूप से पूर्वी खासी हिल्स (ईकेएच) के साथ अतिरिक्त 60 नई मोटरसाइकिलें प्रदान की जाएंगी।

उत्तराखंड की उभरती चुनौतियाँ - पुलिसिंग तंत्र में सुधार

- डॉ. प्रमोद कुमार सिन्हा

मेघालय अपने नागरिक केंद्रित शासन मॉडल के लिए देश की अग्रणी सरकारों में से एक हो सकता है। कॉनराड संगमा की सरकार वास्तव में "अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार" के दर्शन के अनुसार राज्य मशीनरी को तैयार करने की कोशिश कर रही है। 2020 में मेघालय सरकार ने एक अधिनियम बनाया था - "मेघालय लोक सेवा का अधिकार अधिनियम 2020" इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार के सभी संबंधित विभाग नागरिकों के हित में कार्य करने और कार्य करने के लिए बाध्य हैं।

मेघालय लोक सेवा अधिकार अधिनियम 2020 के तहत 100 से अधिक सेवाएं शामिल हैं। मेघालय राज्य विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाले हैं और सरकार के वर्तमान गठबंधन सहयोगी अपने प्रदर्शन के आधार पर जनादेश पाने के लिए आश्वस्त हैं। लॉन्च के दौरान बोलते हुए, संगमा ने कहा कि राज्य प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय कर रहा है कि हर विभाग में नागरिक केंद्रित शासन लागू किया जा रहा है।

"कई बार कुशलतापूर्वक और तेजी से वितरण करने की मूल अवधारणा से ध्यान भटक जाता है क्योंकि अधिकांश समय लक्ष्य प्राप्त करने और योजनाओं को लागू करने, दिशानिर्देशों का पालन करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है।"

नियम यह है कि हम भूल जाते हैं कि हम यहां लोगों की सेवा करने के लिए हैं, "उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि एकीकृत वेब पोर्टल नागरिक-केंद्रित शासन प्राप्त करने और समग्र वितरण तंत्र में सुधार की दिशा में एक कदम है। "सभी 188 सेवाओं को जल्द से जल्द पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए," - उन्होंने उल्लेख किया और सभी स्तरों पर विभागों से समयसीमा का पालन करने का आग्रह किया ताकि कोई देरी न हो।

यह ध्यान देने योग्य है कि 'मेघालय लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2020' निर्धारित समय सीमा के भीतर नागरिकों को अधिसूचित सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी की देखभाल करने के लिए एक अधिनियम है, जिसमें डिफॉल्ट के मामले में सरकारी सेवाओं की देनदारियां भी शामिल हैं। यह पोर्टल नागरिकों को अधिकतम सुविधा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह एक एकीकृत वेब पोर्टल और अधिकारियों और आयोग के लिए एक डैशबोर्ड है जो प्रत्येक चरण में सभी आवेदनों की स्थिति की निगरानी करने में सक्षम बनाता है।

एक आधिकारिक बयान में बताया गया, "खराब नेटवर्क कनेक्टिविटी वाला नागरिक सामान्य सेवा केंद्रों में पोर्टल की सेवाओं का लाभ उठा सकता है।"

नागरिक केंद्रित शासन प्राप्त करने की दिशा में यह एक क्रांतिकारी कदम है और सरकार सरकारी विभागों द्वारा नागरिकों को सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी के प्रावधान के माध्यम से जो हासिल करने की कोशिश कर रही है, उसके मूल में है। मेघालय सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है कि कई ई-गवर्नेंस पहले सीधे नागरिकों के दरवाजे तक पहुंचें, जिससे ये सेवाएं सभी के लिए सुलभ हो जाएं, यहां तक कि दूरदराज के स्थानों पर रहने वाले लोगों के लिए भी।

जनता के सामने आने वाली बाधाओं को ध्यान में रखते हुए, मेघालय के मुख्यमंत्री - कॉनराड संगमा ने 5 ऑनलाइन सेवाएं भी शुरू की हैं - विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री की सामाजिक सहायता योजना; राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन नागरिक-केंद्रित सेवा; राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली (एनजीडीआरएस); एमटीसी बस सेवाओं के लिए ई-टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग; वार्षिक संपत्ति रिटर्न ऑनलाइन जमा करना।

इसके अलावा, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के तहत राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन नागरिक-केंद्रित सेवा - राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली (आरसीएमएस) डिजिटल रूप से सक्षम पीडीएस का एक हिस्सा है, जो नागरिकों को परिवार के विवरण, आधार सीडिंग, स्थानांतरण/सरेंडर को संशोधित करने की अनुमति देती है। राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली (एनजीडीआरएस) - राजस्व विभाग के तहत एक पहल, नागरिकों को साक्ष्य के संरक्षण, स्वामित्व के आश्वासन, दस्तावेजों के प्रचार और धोखाधड़ी की रोकथाम के उद्देश्य से, पंजीकरण प्राधिकरण के साथ भूमि दस्तावेजों को पंजीकृत करने में सक्षम बनाएगी।

चिंता के मुद्दे: संक्षिप्त विवरण

निम्नलिखित टिप्पणियों और विकासों के साथ राज्य के 13 जिलों में से 11 में राजस्व और पुलिसिंग की दोहरी भूमिका के साथ पटवारियों द्वारा की जाने वाली राजस्व पुलिस प्रणाली की वर्तमान प्रथाओं और तंत्र पर चिंता व्यक्त की गई है:

2018 में, न्यायालय ने यह ध्यान में रखते हुए राजस्व पुलिस प्रणाली को समाप्त करने का आदेश दिया था कि अधिकारी समसामयिक अपराधों से निपटने में प्रशिक्षित नहीं हैं और आगे यह आरोप लगाया गया था कि राजस्व अधिकारी जांच में गड़बड़ी करते हैं।

2022 में, माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य के मुख्य सचिव को आपराधिक मामलों या पुलिस गतिविधियों को संभालने वाले पटवारियों की वर्तमान प्रथाओं को दूर करने के लिए राज्य द्वारा किए गए या किए जाने की संभावना वाले प्रयासों पर अद्यतन करने के लिए कहा।

मौजूदा तंत्र में, राजस्व विभाग के कर्मियों, जैसे, पटवारी और कानूनगो, पुलिस की भूमिका के साथ आपराधिक जांच की प्रारंभिक परत बनाते हैं। हालाँकि, हाल ही में अकिता भंडारी मामले में, जैसा कि उसके माता-पिता ने बताया है, मामला कथित तौर पर कमजोर हो गया क्योंकि पटवारी ने तुरंत कार्रवाई नहीं की, जिससे आरोपी सबूत नष्ट करने और फिर भागने में सक्षम हो गया।

वर्तमान प्रथाओं के अनुसार, जब भी कोई अपराध होता है या उसके संज्ञान में आता है, तो क्षेत्र की राजस्व पुलिस (पटवारी) एफआईआर दर्ज करती है, मामले की जांच करती है, आरोपी को गिरफ्तार करती है और स्थानीय अदालत में आरोप पत्र दाखिल करती है। हालाँकि, जघन्य अपराधों की सूचना मिलने पर मामले को एक सप्ताह में 10 दिन के भीतर नियमित पुलिस को स्थानांतरित करने का प्रावधान पहले से ही मौजूद है।

हालिया घटना ने राज्य की न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों का गंभीरता से ध्यान आकर्षित किया है। राजस्व और नियमित पुलिस दोनों की उपस्थिति और भागीदारी के बावजूद, यह महसूस किया गया है कि नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा पर त्वरित ध्यान देने के लिए प्रचलित प्रणाली की समीक्षा की आवश्यकता हो सकती है।

प्रश्न उठता है; क्या राजस्व पुलिस को समाप्त करना नियमित पुलिस द्वारा उत्तराखंड राज्य में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को संबोधित करने के लिए पर्याप्त होगा या समग्र दृष्टिकोण से बदलाव को बेहतर रूप दिया जाएगा? राज्य की जनसांख्यिकी को ध्यान में रखना होगा, विशेषकर उत्तराखंड के पहाड़ी लोगों के शांतिप्रिय सरल स्वभाव को। साथ ही सामाजिक ताने-बाने में हो रहे बदलावों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, जहां अधिक से अधिक मोबाइल और कंप्यूटर-आधारित संस्कृति सामाजिक दूरी को बढ़ावा दे रही है और इसलिए, बदलाव या सामाजिक एजेंटों की आवश्यकता है जो इन अंतरों को पाट सकें। इस संबंध में, विश्व स्तर पर कुछ देशों से भी सबक लिया जा सकता है, जहां सामुदायिक पुलिसिंग को उनकी उपस्थिति और समाज का अभिन्न अंग होने, स्थानीय लोगों से परिचित होने, उनकी जरूरतों को समझने और जांच प्रक्रिया में खुलेपन के लिए प्राथमिकता दी जाती है। नियमित पुलिस द्वारा यादृच्छिक गश्त। ये प्रथाएं उत्तराखंड राज्य में नए तंत्र और प्रणाली के निर्माण में मदद कर सकती हैं।



उत्तराखंड में पुलिसिंग की समीक्षा

पहाड़ी क्षेत्रों या ग्रामीण भारत के प्रशासन की अपनी ताकत और चुनौतियाँ हैं। छोटे इलाकों या गांव से लेकर जिला स्तर तक, अधिकारियों की कई परतें होती हैं और ऐसे क्षेत्रों का सामाजिक ताना-बाना जीवन जीने के समाजवादी पैटर्न का अभिन्न अंग है। ऐसे क्षेत्रों में संचार सामाजिक रूप से जुड़े हुए स्तरों, जैसे पटवारियों या राय नेताओं के माध्यम से गांव से तहसील तक चलता है।

शायद इन चुनौतियों को पहचानते हुए, पटवारियों को उनके अधिकार क्षेत्र के ऐसे दूरदराज के क्षेत्रों में राजस्व संग्रह और पुलिसिंग की दोहरी भूमिका दी गई थी। उत्तराखंड, भारत का एकमात्र पहाड़ी राज्य, एक अद्वितीय पुलिस प्रणाली के लिए जाना जाता है जिसमें राजस्व विभाग के नागरिक अधिकारियों के पास पुलिस की शक्तियाँ और कार्य होते हैं, जिसे 18 वीं - 19 वीं शताब्दी में शुरू किया गया था।

यद्यपि राज्य में नियमित पुलिस स्थापित है, फिर भी कई हिल पट्टियों में, राज्य के 13वें जिलों में से 11 के आधे से अधिक क्षेत्र में, पुलिस का अधिकार क्षेत्र राजस्व अधिकारियों के पास है, जो गिरफ्तारी जैसे पुलिस के कार्य करते हैं। अपराधी और जांच। ऐतिहासिक रूप से, यह भी स्पष्ट था कि इनमें से कई हिस्सों में अपराध बहुत कम होते थे और कमाऊ जैसे क्षेत्र में विशेष या नियमित पुलिस की आवश्यकता नहीं होती थी। हालाँकि, अल्मोडा, रानीखेत और नैनीताल आदि शहरों में नियमित पुलिस मौजूद है।

अपराधों से संबंधित जांच और संबद्ध मामलों के प्रयोजन के लिए, राजस्व अधिकारी संहिता के तहत एक पुलिस अधिकारी को सक्षम मानेंगे। फिर, यह ध्यान दिया जा सकता है कि राजस्व अधिकारियों की ऐसी विशेष शक्तियाँ और कार्य केवल उन्हीं क्षेत्रों में प्रभावी हैं जहाँ नियमित पुलिस का अधिकार क्षेत्र विस्तारित नहीं है और हर जगह नहीं।

उत्तराखंड में मौजूदा तंत्र में, राजस्व पुलिस (पटवारी) गंभीर अपराधों या अपराधों के मामलों को स्थानीय अदालत के माध्यम से एक सप्ताह या 10 दिनों के भीतर नियमित पुलिस को स्थानांतरित कर देती है। यह समय-सीमा चिंताजनक है और ऐसे मामलों के 24 घंटों के भीतर या अधिकतम 48 घंटों के भीतर त्वरित समाधान के लिए तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

वर्तमान में, राजस्व पुलिस का प्रबंधन तुलनात्मक रूप से कम जनशक्ति द्वारा किया जाता है, जो स्वीकृत शक्ति का केवल 61% है। अपने सीमित संसाधनों के साथ वे लगभग एक शताब्दी से ऐसा कर रहे हैं और इसलिए वास्तव में ध्यान देने की आवश्यकता है, चाहे वह कौशल के रूप में हो, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे के साथ अद्यतन करना हो या बेहतर सेवा देने और परिचालन दक्षता में सुधार करने के लिए मुख्यधारा की पुलिसिंग के साथ जुड़ना हो।

जैसा कि हम जानते हैं, लोक सेवा, चाहे वह पुलिस हो या राजस्व पुलिस, अक्सर विभिन्न कारणों से आलोचना का विषय होती है, जिसमें लोगों और उनकी संपत्ति की सुरक्षा को संबोधित करने में इसकी अप्रभावीता भी शामिल है।



विश्व स्तर पर, पुलिस व्यवस्था में आमूल-चूल बदलाव आ रहा है। दुनिया भर के कई देश स्पष्ट कारणों से या तो पारंपरिक पुलिसिंग से समुदाय-आधारित पुलिसिंग की ओर बढ़ रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वह अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया हो, जिसमें जांच प्रक्रिया और वैकल्पिक रणनीतियों में खुलापन, बेहतर सार्वजनिक समर्थन शामिल है। सामुदायिक समस्याओं और जरूरतों की पहचान, सामुदायिक संबंध बनाना, मोबाइल और कंप्यूटर-आधारित डेटा पर कम निर्भरता और अधिक प्रत्यक्ष संपर्क, आदि।

उत्तराखंड की राजस्व पुलिसिंग की मौजूदा व्यवस्था में आवश्यकता आधारित बदलाव लाने के लिए कुछ देशों की प्रचलित प्रथाओं से सबक लेना होगा। उदाहरण के लिए, जापान के 'पुलिस बॉक्स' के लाभ, जो सामुदायिक पुलिस के संचालन और स्थानीय लोगों की स्थिति, जरूरतों, दृष्टिकोण और चिंताओं को समझने में मदद करने के लिए स्थापित किए गए हैं। सामुदायिक पुलिसिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया में सफल कार्यक्रम विभिन्न कारणों से घर से दूर रहने वाले स्थानीय लोगों की मदद के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इसलिए, 'सामुदायिक पुलिसिंग' को नागरिक और पुलिसिंग आवश्यकताओं के बीच अंतर को पाटने के लिए पहचाना जा रहा है, जिससे पुलिसिंग एजेंट समाज से अभिन्न हो जाते हैं और इसे कम भावनात्मक जुड़ाव के साथ यादृच्छिक गश्त के लिए एक सेट अप के रूप में नहीं देखा जाता है। 'पटवारियों' की कार्यप्रणाली सामुदायिक पुलिसिंग के बहुत करीब है, यदि उनकी ताकत का उपयोग पर्याप्त प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचा प्रदान करके और नियमित पुलिस प्रणाली का हिस्सा लाकर सामुदायिक पुलिसिंग के मॉडल के अनुरूप किया जा सकता है, जहां तक कानून और व्यवस्था का सवाल है।

जहां तक स्थानीय लोगों के साथ दिन-प्रतिदिन के संचार का सवाल है, वर्दी में पुलिस के अपने स्वयं के स्थापित गुण और अवगुण हैं, इसकी कथित आक्रामक प्रकृति या दृष्टिकोण उन्हें दूर कर देता है और आम तौर पर लोग पुलिस के करीब या खुले होने से डरते हैं। ऐसे कारणों से वर्दी, 'सिविल ड्रेस' में व्यक्ति आसानी से स्थानीय लोगों और समुदाय के साथ घुल-मिल सकता है और लोग अपनी चिंताओं को साझा करने में निडर महसूस करते हैं और इस तरह प्रशासनिक व्यवस्था के लिए आवश्यक सभी संभावित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए वर्दी में पुलिस की मौजूदगी भी जरूरी है। गंभीर अपराधों को रोकने और सख्त कानून व्यवस्था के लिए वर्दी में पुलिस प्रभावी हो सकती है। इस प्रकार, दोनों एक नई उभरती पुलिस व्यवस्था का हिस्सा बनकर एक-दूसरे के पूरक बन सकते हैं। इसलिए, दोनों का संयोजन बेहतर उद्देश्य पूरा करेगा और विकसित होने वाले नए तंत्र में विवेकपूर्ण ढंग से रखा जाएगा।

उत्तराखंड में पुलिस व्यवस्था की मौजूदा व्यवस्था में सुधार की जरूरत

समय बीतने के साथ, किसी भी प्रणाली की समीक्षा अपरिहार्य है, वैसे ही उत्तराखंड राज्य में राजस्व या पटवारी संचालित पुलिसिंग की भी होगी, जो पीड़ित के दर्द और परिवार की पीड़ा को पहचानते हुए चिंता का विषय रहा है। साथ ही, पुलिसिंग के नए मॉडल की सुचारु सुविधा के लिए किसी भी प्रणाली की ताकत को नए सेटअप में बरकरार रखा जा सकता है, साथ ही 'सामुदायिक पुलिसिंग' की वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से सबक भी लिया जा सकता है।

जैसा कि अनुसूचित जिला अधिनियम, 1874, उसमें बनाए गए नियम और 1916 के अधिनियम आदि अन्य बातों के साथ-साथ पुलिसिंग कार्य के निर्वहन के लिए राजस्व अधिकारियों के दायरे को परिभाषित करते हैं और नियमों के नियम 1 के रूप में '1861 के अधिनियम वी में नामांकित पुलिस के अलावा ...' तात्पर्य यह है कि यह एक विचार देता प्रतीत होता है कि राजस्व पुलिस प्रणाली नियमित पुलिस के अलावा नहीं बल्कि उसके अपमान में बनाई गई थी और यह वहां काम करेगी जहां नियमित पुलिस का क्षेत्राधिकार विस्तारित नहीं होता है।

इसलिए, एक सदी से अधिक की अवधि में उत्तराखंड राज्य में बनाए गए विकसित अधिनियमों और रूपरेखाओं की समीक्षा करने की आवश्यकता है, जिसने राजस्व अधिकारियों को गिरफ्तार करने और जांच करने की शक्ति दी ताकि एक नया तंत्र लाया जा सके जो प्रभावी ढंग से काम करता हो। माननीय उच्च न्यायालय की आशंकाओं और राज्य के अधिकारियों के लिए बेहतर कार्य, कहते हैं:

1. मूल्यांकन में उस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखा जाना चाहिए जिसमें 1916 के 'कुमाऊं पुलिस' नियम अनुसूचित जिला अधिनियम, 1874 के तहत बनाए गए थे जो वर्तमान जिलों अल्मोडा, बागेश्वर, चंपावत, चमोली, पिथौरागढ़, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और पहाड़ी पट्टियों पर लागू होते हैं। जिला नैनीताल।
2. फिर से, टिहरी गढ़वाल राजस्व अधिकारी (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1956 और जौनसार-बावर परगना (जिला देहरादून) राजस्व अधिकारी (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 जो टिहरी और उत्तरकाशी जिलों और जौनसार-बावर में संचालित होते हैं। क्रमशः जिला देहरादून के परगने।
3. उत्तराखंड पुलिस अधिनियम, 2007

वर्दी में पुलिस की उपस्थिति और निकटता, बलपूर्वक ताकत रखने या प्रदर्शित करने से सिविल वर्दी में सामुदायिक पुलिस की उपस्थिति के साथ विवेकपूर्ण रूप से संतुलन बनाने में मदद मिलेगी, जहां मौजूदा पटवारियों की ताकत बेहतर उद्देश्य प्रदान कर सकती है और समाज के लिए संतुलन बल के रूप में दोनों की उपस्थिति की आवश्यकता होती है।



हाल की घटना से सबक लेते हुए, पीड़ित के दर्द और परिवार की पीड़ा को समझते हुए, स्थिति राज्य के नागरिकों के हित में समग्र रूप से व्यवस्था में बदलाव की मांग करती है ताकि एक नई व्यवस्था बनाई जा सके जो नागरिकों का विश्वास पैदा करे। इसलिए, बदलाव को 'राजस्व और नियमित पुलिसिंग' की दोनों प्रणालियों की ताकत को शामिल करते हुए क्रियान्वित किया जाना चाहिए और इसे बेहतर प्रशिक्षण, नवीनतम पुलिसिंग बुनियादी ढांचे से लैस, पर्याप्त जनशक्ति और देरी करने में शामिल व्यक्तियों को सबक देने के लिए कठोर निर्णयों के माध्यम से 'सामुदायिक पुलिसिंग' में आकार दिया जाना चाहिए। न्याय और नागरिक की सुरक्षा या सम्मान के साथ खेलवाड़। राजस्व पुलिसिंग के सकारात्मक गुणों में निकटता शामिल है समुदाय, स्थानीय लोगों की चिंताओं को समझना, अंगूर, सामुदायिक मामलों में भागीदारी, समुदाय, स्थानीय लोगों का विश्वास और क्षमता निर्माण और विश्वास निर्माण का माहौल बनाना नए सेंटअप में अपराधियों से निपटने के लिए हार्ड कोर नियमित पुलिस ताकत के साथ बड़ी ताकत होगी। और समाज को परेशान करने वाले तत्व इसलिए, वर्तमान प्रथाओं को समाप्त करने के बाद, पुलिसिंग का नया तंत्र कानूनगो सहित पटवारियों को राजस्व और पुलिसिंग की दोहरी भूमिका के साथ परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में उनकी भूमिका को परिभाषित करने और पुलिस व्यवस्था में विधिवत प्रशिक्षित और सुसज्जित करने में सक्षम बना सकता है। पुलिसिंग के लिए, वे 'सामुदायिक पुलिस' यानी 'नियमित पुलिसिंग' की नई शाखा का हिस्सा होंगे, जहां उन्हें राज्य कानूनों, आपराधिक जांच, गश्ती प्रक्रियाओं, आग्नेयास्त्र प्रशिक्षण के क्षेत्रों में अन्य पुलिस निरीक्षकों और अधिकारियों के साथ प्रशिक्षित किया जाएगा। यातायात नियंत्रण, रक्षात्मक ड्राइविंग में क्षमता निर्माण, आत्मरक्षा, प्राथमिक चिकित्सा, कंप्यूटर कौशल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), निगरानी और अपराध रोकथाम के क्षेत्रों में उपकरण, साइबर अपराध सहित प्रौद्योगिकी संचालित समाधान, शारीरिक प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षाओं के साथ फील्डवर्क। ऐसी पोस्टिंग के लिए उपयुक्तता के लिए उनकी दक्षता का मूल्यांकन करें। स्थिति पुलिसिंग प्रणाली को विकसित करने के लिए पाठ्यक्रम के एक नए मॉड्यूल की मांग कर सकती है जिसमें समुदाय और नियमित पुलिसिंग दोनों की ताकत हो जो उन्हें 'सुरक्षा और लोग पहले' दृष्टिकोण के साथ त्वरित कार्रवाई करने में सक्षम बनाती है।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, 'पटवारियों द्वारा राजस्व पुलिसिंग' को समाप्त करने से परे होने वाली संभावित व्यवधानों की सराहना करते हुए, समय-समय पर बनाई गई रूपरेखाओं का एक व्यापक दृष्टिकोण 'सामुदायिक पुलिसिंग' और कौर पर वैश्विक प्रथाओं के सबक के साथ समन्वयित किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य में पुलिसिंग का एक नया मॉडल बनाने के लिए नियमित पुलिस की ताकत। एक बार सफलतापूर्वक लागू होने पर यह अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए एक अनुकरणीय मॉडल साबित हो सकता है। राज्य पुलिस व्यवस्था के लंबे इतिहास, उभरती चुनौतियों, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव या सरकार के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करना दृढ़ता से महसूस किया जाता है। भारत के सिस्टम और समाज के विभिन्न वर्गों से आने वाले अन्य सदस्यों के साथ एक निर्धारित समय सीमा में व्यापक दृष्टिकोण अपनाने और उत्तराखंड राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए:

अध्यक्ष: उत्तराखंड या यूपी सरकार के पूर्व मुख्य सचिव या सरकार के सचिव। भारत की।

1. समिति के सदस्य:
2. उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ अधिकारी (प्रमुख सचिव के पद से नीचे नहीं),
3. पुलिस का प्रतिनिधि (आईजी रैंक से नीचे का नहीं),
4. मानवाधिकार के प्रतिनिधि (वरिष्ठ कार्यकर्ता या सेवानिवृत्त सदस्य) और
5. कानून पृष्ठभूमि के शिक्षाविद (प्रोफेसर के पद से नीचे नहीं) या उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिष्ठित वकील/अर्टोर्नी (सेवानिवृत्त)।
6. लोक प्रशासन पृष्ठभूमि से शिक्षाविद (प्रोफेसर के पद से नीचे नहीं) या सिविल सोसायटी से प्रतिष्ठित व्यक्ति
7. सचिव, विधि विभाग - सदस्य सचिव

समिति का दायरा:

मौजूदा तंत्र, विभिन्न अधिनियमों, ढांचे, अंतराल, मामलों के पंजीकरण की गति और मामलों के प्रशासन, सामुदायिक पुलिसिंग की सर्वोत्तम प्रथाओं और अन्य वैश्विक प्रथाओं की निगरानी करना और आगे बढ़ना जो माननीय उच्च न्यायालय की चिंता को संबोधित कर सकता है, साथ ही सौहार्दपूर्ण ढंग से संतुलन भी बना सकता है। पुलिसिंग तंत्र में नागरिक को चेहरे और आधारशिला के रूप में रखें। सरकार को रिपोर्ट सौंपने की समय सीमा: 6 महीने।

अतीत से सबक

केस स्टडी 1: 1990 के दशक में बैंगलोर, भारत में सार्वजनिक सेवा वितरण पर रिपोर्ट कार्ड

विश्व बैंक केस स्टडीज से प्रेरित जिसका शीर्षक है "बजट और सार्वजनिक व्यय प्रबंधन में भागीदारी दृष्टिकोण"

पृष्ठभूमि

1993 में, बैंगलोर में व्यक्तियों का एक छोटा समूह सार्वजनिक सेवाओं में गिरावट के बारे में चिंतित था और उसने उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया इकट्ठा करने के लिए एक परियोजना शुरू की। उन्होंने इस फीडबैक का उपयोग एक रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए किया, जिसमें गुणवत्ता, दक्षता और पर्याप्तता के बारे में उपयोगकर्ताओं की धारणाओं के आधार पर शहर में प्रमुख सेवा प्रदाताओं के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया। परिणामों ने संतुष्टि और भ्रष्टाचार का एक मात्रात्मक माप दिखाया, जिसे मीडिया कवरेज मिला और सुधार के लिए नागरिक और सरकार दोनों का समर्थन प्राप्त हुआ। रेटेड एजेंसियों ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए काम किया।

1999 में, इस परियोजना को दोहराया गया और अंततः अगले कुछ वर्षों में पांच अन्य भारतीय शहरों और कर्नाटक राज्य में दोहराया गया। रिपोर्ट कार्ड ने सार्वजनिक प्रतिक्रिया एकत्र करने और साझा करने के लिए एक व्यवस्थित तरीका प्रदान किया और सरकारी स्वामित्व वाली एजेंसियों जैसे एकाधिकार में प्रतिस्पर्धा के विकल्प के रूप में कार्य किया, जो निजी उद्यमों की तरह अपने ग्राहकों की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी नहीं हो सकते हैं। इन रिपोर्ट कार्डों ने नागरिकों को सामूहिक रूप से और विश्वसनीय रूप से एजेंसियों को यह बताने की अनुमति दी कि वे कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं और बदलाव के लिए दबाव डाल रहे हैं।

पहल

1993 में, बैंगलोर में व्यक्तियों का एक छोटा समूह सार्वजनिक सेवाओं में गिरावट के बारे में चिंतित था और उसने उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया इकट्ठा करने के लिए एक परियोजना शुरू की। उन्होंने इस फीडबैक का उपयोग एक रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए किया, जिसमें गुणवत्ता, दक्षता और पर्याप्तता के बारे में उपयोगकर्ताओं की धारणाओं के आधार पर शहर में प्रमुख सेवा प्रदाताओं के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया। परिणामों ने संतुष्टि और भ्रष्टाचार का एक मात्रात्मक माप दिखाया, जिसे मीडिया कवरेज मिला और सुधार के लिए नागरिक और सरकार दोनों का समर्थन प्राप्त हुआ। रेटेड एजेंसियों ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए काम किया।

1999 में, इस परियोजना को दोहराया गया और अंततः पांच अन्य भारतीय शहरों और राज्य में दोहराया गया अगले कुछ वर्षों में कर्नाटक। रिपोर्ट कार्ड ने सार्वजनिक प्रतिक्रिया एकत्र करने और साझा करने के लिए एक व्यवस्थित तरीका प्रदान किया और सरकारी स्वामित्व वाली एजेंसियों जैसे एकाधिकार में प्रतिस्पर्धा के विकल्प के रूप में कार्य किया, जो निजी उद्यमों की तरह अपने ग्राहकों की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी नहीं हो सकते हैं। इन रिपोर्ट कार्डों ने नागरिकों को सामूहिक रूप से और विश्वसनीय रूप से एजेंसियों को यह बताने की अनुमति दी कि वे कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं और बदलाव के लिए दबाव डाल रहे हैं।

पहल से निष्कर्ष

पहली और दूसरी रिपोर्ट कार्ड पहल के बीच, टेलीफोन और अस्पतालों जैसी सेवाओं में कुछ सुधार हुए, लेकिन कुल मिलाकर, नागरिक अभी भी सार्वजनिक सेवाओं से संतुष्ट नहीं थे। यह विशेष रूप से कर्मचारियों के ग्राहकों के साथ बातचीत करने के तरीके के लिए सच था। उच्चतम संतुष्टि रेटिंग 67% होने के बावजूद, बेंगलूर टेलीकॉम का स्कोर उन लोगों के बीच तेजी से गिरकर 30% हो गया, जिन्हें किसी समस्या को हल करने के लिए एजेंसी कर्मियों के साथ बातचीत करनी थी। भ्रष्टाचार की धारणा बढ़ गई थी, अधिक लोग रिश्वत दे रहे थे और बड़ी रकम दी जा रही थी। अधिकांश लोग समस्याओं के समाधान के लिए व्यक्तिगत रूप से एजेंसियों के पास जाते थे और अक्सर उन्हें कई दौर करने पड़ते थे। रिश्वतखोरी के आधे से अधिक मामले जबरन वसूली के थे, जबकि एक तिहाई स्वैच्छिक "त्वरित" भुगतान थे।

1999 में झुग्गीवासियों पर एक अलग रिपोर्ट में पाया गया कि वे पुलिस, जल आपूर्ति और कचरा हटाने की तुलना में परिवहन, स्कूल, बिजली और अस्पतालों जैसी सेवाओं से अधिक खुश थे। शहरी गरीबों को समस्याओं के समाधान के लिए मध्यम वर्ग की तुलना में अधिक बार एजेंसियों के पास जाना पड़ता था और उनकी समस्या समाधान दर कम थी, लेकिन वे अपनी कम अपेक्षाओं के कारण सेवाओं से अधिक संतुष्ट दिखते थे। सेवाओं तक पहुंचने के लिए रिश्वत देने वाले लोगों का अनुपात मध्यम आय वर्ग की तुलना में गरीबों में अधिक था। 1993 में, शहरी गरीबों में से एक तिहाई ने रिश्वत देने की सूचना दी, जो पांच साल बाद घटकर 25% हो गई, लेकिन भुगतान की गई औसत राशि तीन गुना बढ़कर रु. 1245, अधिकतर पुलिस को।

रिपोर्ट कार्ड में गैर-पारदर्शी प्रक्रियाओं और अधिकारियों की मनमानी निर्णय लेने की शक्तियों के साथ सेवा प्रदाताओं में छोटे भ्रष्टाचार और अक्षमता के बीच संबंध का पता चला। इन समस्याओं के समाधान के लिए सूचना तक पहुंच में सुधार, सेवा मानकों और ग्राहक अधिकारों को निर्दिष्ट करने और संस्थागत रिपोर्ट कार्ड पहल के माध्यम से प्रदर्शन की निरंतर सार्वजनिक जांच और निगरानी सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया था।

रिपोर्ट कार्ड का प्रभाव

रिपोर्ट कार्ड की शुरुआत के परिणामस्वरूप सार्वजनिक एजेंसियों के व्यवहार में बदलाव आया जो पहले उदासीन थीं। उन्होंने नागरिकों की चिंताओं को सुनना और उन पर प्रतिक्रिया देना शुरू किया। धारणाओं के परिमाणिकरण ने संतुष्टि के स्तर का एक विश्वसनीय संकेतक प्रदान किया, जिससे अंतर-एजेंसी तुलना की अनुमति मिली और आंतरिक सुधारों को गति मिली। हालाँकि 1994 से 1999 तक सेवा की गुणवत्ता में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ, लेकिन कुछ एजेंसियों ने जनता के असंतोष पर प्रतिक्रिया व्यक्त की।

सबसे खराब रेटिंग वाली एजेंसी, बेंगलूर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सेवा वितरण के लिए अपने सिस्टम की समीक्षा करने और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी समस्याओं के समाधान पर परामर्श के लिए बेंगलूर नगर निगम के साथ एक संयुक्त मंच की मेजबानी करने जैसे बदलाव किए। हालाँकि, रिपोर्ट कार्ड पहल के पूरक के लिए राजनीतिक सुधारों की आवश्यकता को प्रदर्शित करते हुए, सभी एजेंसियां उत्तरदायी नहीं थीं। रिपोर्ट के निष्कर्षों की मीडिया कवरेज के कारण सेवा वितरण और भ्रष्टाचार के मुद्दों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ी। नागरिक समाज समूहों को एहसास हुआ कि उनका सामूहिक दबाव बदलाव ला सकता है। रिपोर्ट कार्ड ने शहरी जीवन को बेहतर बनाने के लिए बेंगलूर में राज्य-नागरिक स्वाभिमान पहल जैसी पहल को प्रेरित किया। दूसरे रिपोर्ट कार्ड में शहर की सेवाओं और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए बेंगलूर एजेंडा टास्क फोर्स का गठन किया गया। रिपोर्ट कार्ड ने नागरिक समाज सक्रियता के विकास को प्रेरित किया और इसे अन्य भारतीय शहरों और अंतर्राष्ट्रीय स्थानों में दोहराया गया। नगरपालिका स्तर पर रिपोर्ट कार्ड की सफलता ने कर्नाटक राज्य के स्वास्थ्य विभाग को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं में सेवाओं की गुणवत्ता पर मरीजों से प्रतिक्रिया लेने के लिए प्रेरित किया। निष्कर्षों की वैधता के बारे में सतर्क रहना और स्थानीय समस्याओं को हल करने के लिए या इसके विपरीत राष्ट्रव्यापी डेटा का उपयोग करने से बचना महत्वपूर्ण था।

निगरानी तंत्र के रूप में रिपोर्ट कार्ड की सीमा रिपोर्ट कार्ड जनमत सर्वेक्षणों से भिन्न होते हैं क्योंकि वे साक्षात्कार लेने वालों के वास्तविक अनुभवों को दर्शाते हैं। इसे एक मूल्यवान पहलू माना जाता था, लेकिन आय, शिक्षा और क्षेत्र जैसी सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं में अलग-अलग संतुष्टि स्तरों के आधार पर एक समूह की सामान्य धारणा को निर्धारित करना एक चुनौती के रूप में पहचाना गया था। हालाँकि, समान सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए नमूने को उचित रूप से अलग करके इस चुनौती को कम किया जा सकता है। अतीत में, रिपोर्ट कार्ड मुख्य रूप से सेवा की गुणवत्ता पर केंद्रित थे लेकिन ग्रामीण और स्लम क्षेत्रों में पहुंच के मुद्दों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया। रिपोर्ट कार्ड को लागू करने के लिए तकनीकी कौशल, वित्तपोषण, समय और स्थानीय हित के साथ-साथ एक अनुकूल सामाजिक-राजनीतिक वातावरण वाले सक्षम मध्यस्थ की आवश्यकता होती है। विकासशील देशों में, प्रक्रिया को लागत प्रभावी और प्रबंधनीय बनाने में नमूना आकार को कम करने जैसे समझौते शामिल हो सकते हैं, जो रिपोर्ट की विश्वसनीयता से समझौता कर सकता है। सूचना और कार्रवाई के बीच संबंध सुनिश्चित करना, गैर-सरकारी स्तरों पर प्रक्रिया को संस्थागत बनाना और नागरिक समाज की निगरानी को सशक्त बनाने के लिए रिपोर्ट कार्ड का उपयोग करना दीर्घकालिक प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण विचार थे।

प्रकृति के लिए मॉडल

चरण 1: योजना और तैयारी

- सेवा उपयोगकर्ताओं, नागरिकों और ग्राहकों के साथ छोटे मामले का अध्ययन और समूह चर्चा आयोजित करना
- घरों का एक प्रतिनिधि नमूना चुनना, जिसे संभवतः स्थान, जैसी श्रेणियों में विभाजित किया गया है।
- आय समूह, लिंग, जातीयता और शिक्षा स्तर
- पूर्व-परीक्षण चरण 2 के आधार पर सेवा वितरण पर प्रश्नावली को संशोधित और अंतिम रूप देना: सांख्यिकीय और विश्लेषणात्मक कार्य
- व्यक्तियों का सर्वेक्षण करने के लिए रैंकिंग पद्धति का उपयोग करना
- भ्रष्टाचार जैसे प्रत्येक एजेंसी और मुद्दे के लिए समग्र संतुष्टि रेटिंग की गणना करना
- विश्लेषण और आंकड़ों के साथ समग्र और लघु रिपोर्ट कार्ड बनाना
- प्रेस विज्ञप्ति, मीडिया किट और आसानी से समझने योग्य ब्रीफिंग जैसी अतिरिक्त सामग्री विकसित करना
- टिप्पणियाँ
- चरण 3: प्रसार
- लॉन्च से पहले संबंधित अधिकारियों को मिनी-रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करना
- निष्कर्षों को जनता के सामने जारी करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करना
- सर्वेक्षण की गई एजेंसियों के बीच और के बीच टाउन-हॉल शैली की बैठकों के दो दौर आयोजित करना
- जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों और नागरिकों
- चरण 4: वकालत और निगरानी
- रिपोर्ट कार्ड के निष्कर्षों के निरंतर मीडिया कवरेज को प्रोत्साहित करना
- मुद्दों के समाधान के लिए एजेंसियों द्वारा की गई प्रगति की निगरानी करना और सीधे अनुवर्ती कार्रवाई करना
- 1 से 2 वर्षों के बाद अनुवर्ती रिपोर्ट कार्ड पहल की योजना बनाना, किसी भी खामी को दूर करना और सर्वेक्षण के लिए नए क्षेत्रों पर विचार।

अतीत से सबक

केस स्टडी 2: पुणे नगर निगम की सहभागी बजटिंग

विश्व बैंक संस्थान की रिपोर्ट "शहरी प्रशासन में सामाजिक जवाबदेही: भारतीय केस अध्ययन" से प्रेरित होकर

परिचय

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए शहर के बजट को निर्वाचित परिषदों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। नागरिकों की भागीदारी से बजट बनाने, खर्चों की निगरानी करने की क्षमता बढ़ती है और शहरी सेवाओं के प्रावधान में खुलेपन को बढ़ावा मिलता है। पुणे नगर निगम बेंगलूर में संचालन और वित्त के सार्वजनिक रिकॉर्ड (प्रूफ) के अनुभव से प्रभावित था। बेंगलूर के उदाहरण के बाद, पुणे ने शुरू से ही एक सहभागी बजट मॉडल स्थापित किया और इसे सभी 14 वार्डों में लागू किया। यह मामला सामाजिक जवाबदेही में स्थिरता बनाए रखने की चुनौती को दर्शाता है।

पहल का औचित्य

विकासशील देशों के संदर्भ में, निर्णय लेने में निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका के बावजूद, शहर के विकास के प्रबंधन में निगरानी की सख्त आवश्यकता है। सड़क, पानी और स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे पर खर्च करने से उल्लेखनीय सुधार नहीं होता है। शहर की सरकारों को अक्सर भ्रष्टाचार, सार्वजनिक धन के कुप्रबंधन और अप्रशिक्षित अधिकारियों जैसे मुद्दों का सामना करना पड़ता है। प्रत्यक्ष भागीदारी नागरिकों की भागीदारी से शहर प्रशासन में जवाबदेही बढ़ सकती है और परिणाम बेहतर हो सकते हैं। प्रूफ अभियान से पता चला कि यदि शहर प्रशासन सहयोग करने को तैयार हो तो सामाजिक जवाबदेही हासिल की जा सकती है।

पुणे में, पुणे नगर निगम के पूर्व आयुक्त और बेंगलूर में PROOF की सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने वाले डॉ. नितिन करीर ने इस पहल का नेतृत्व किया। भारत के सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ने नागरिकों को सार्वजनिक अधिकारियों के साथ जुड़ने के लिए कानूनी ढांचा और अवसर प्रदान किया। पुणे में जनवाणी, पर्यावरण शिक्षा केंद्र, स्वच्छ शहरों के लिए राष्ट्रीय सोसायटी, नागरिक चेतना मंच और पड़ोस के समूहों जैसे संगठनों के साथ साझेदारी में पुणे नगर निगम, विशेष रूप से आयुक्त के सहयोग से भागीदारी बजट प्रक्रिया शुरू की गई थी।

कार्यान्वयन की प्रक्रिया

पुणे सहभागी बजट का विकास एक लंबी प्रक्रिया थी जो 2004-05 में शुरू हुई जब नेशनल सोसाइटी फॉर क्लीन सिटीज, मोहल्ला समितियाँ और नागरिक चेतना मंच जैसे नागरिक समाज संगठनों ने पुणे नगर निगम को परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए। जुलाई 2006 में, नगर आयुक्त ने नेशनल सोसाइटी फॉर क्लीन सिटीज द्वारा आयोजित सहभागी बजटिंग पर एक सार्वजनिक बैठक में बात की और परियोजनाओं को प्राथमिकता देने के लिए जनता की और भागीदारी को प्रोत्साहित किया। डॉ. नितिन करीर ने बेंगलूर में पुणे स्थित गैर सरकारी संगठन जनाग्रह और जनवाणी के साथ प्रूफ की बैठकों के परिणामों पर चर्चा की और प्रक्रिया को संस्थागत बनाने के लिए पुणे नगर निगम के साथ बैठकें कीं। हालाँकि कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ, लेकिन साझेदारों ने लोगों के मुद्दों को सामने लाने के लिए मिलकर काम किया।

2006-07 की अवधि के लिए भागीदारी बजट पुणे के 14 प्रशासनिक वार्डों में वार्ड स्तर पर किया गया था और शहरी सामुदायिक विकास विभाग के प्रमुख श्री अशोक कलमकर द्वारा इसकी सुविधा प्रदान की गई थी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य झुग्गीवासियों के लिए विभाग के पड़ोस समूहों के माध्यम से गरीबों को लाभ पहुंचाना था। नगर निगम के निर्वाचित अधिकारियों द्वारा इसे समाप्त करने के प्रयासों के बावजूद, सहभागी बजटिंग अभ्यास का सफल संस्थागतकरण डॉ. नितिन करीर की दृढ़ता के कारण हुआ।

पर्यावरण शिक्षा केंद्र ने तटस्थ सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करने और सहभागी बजट प्रक्रिया के लिए उपकरण विकसित करने के लिए स्नातकोत्तर छात्रों को स्थित और प्रशिक्षित किया। प्रत्येक वार्ड को बुनियादी ढांचे की जरूरतों के लिए 20 लाख रुपये आवंटित किए गए थे, जिसमें सबसे गरीब लोगों के लिए 5 लाख रुपये आरक्षित थे, और इसे प्रतिभागियों पर अपनी परियोजनाओं को प्राथमिकता देने के लिए छोड़ दिया गया था। प्रतिभागियों को निर्णय लेने में मदद करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए, और वार्ड-स्तरीय चर्चाएँ तत्काल जरूरतों को संबोधित करने में प्रभावी पाई गईं। बजट प्राथमिकताओं पर चर्चा के बाद, प्रतिभागियों को प्रश्नावली दी गई जिन्हें परियोजना प्राथमिकताओं पर मतदान करने के लिए मतपत्र के रूप में माना गया।

पुणे की शहरी मलिन बस्तियों में सक्रिय स्वयं सहायता पड़ोस समूहों के नेटवर्क ने सहभागी बजट विचार को संभव बनाया। स्थानीय मीडिया नागरिकों तक पहुंचने में मूल्यवान साबित हुआ और सहभागी बजट प्रक्रिया के पहले वर्ष में नागरिकों में काफी उत्साह देखने को मिला। हालाँकि कोई सार्वजनिक मूल्यांकन उपलब्ध नहीं है, लेकिन तथ्य यह है कि भागीदारी बजट प्रक्रिया अभी भी जारी है, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि बेंगलूर का पिछला अनुभव सफल नहीं हुआ था।

पुणे के मॉडल की तुलना में बेंगलूर का प्रमाण प्रूफ, बेंगलूर के संबंध में पुणे की सफलता को समझने के लिए, निम्नलिखित कारकों पर विचार करना महत्वपूर्ण है:

- पुणे ने बॉटम-अप दृष्टिकोण का उपयोग करके शुरुआत की संबोधित करने के उद्देश्य से वार्ड बैठकों के माध्यम से नागरिकों की चिंता।
- इस पहल को शहर के अधिकारियों द्वारा संचालित किया गया था नगर निगम आयुक्त अहम भूमिका निभा रहे हैं भूमिका।
- इसमें शामिल भागीदार अपनी भूमिका से अवगत थे बड़ी तस्वीर में और पर ध्यान केंद्रित किया

वहनीयता

- नगर में गरीब वर्ग अधिक थे
- हितधारकों के रूप में शामिल होने की संभावना है, और उनकी भागीदारी को पड़ोस के समूहों में शामिल करके और सबसे वंचितों के लिए धन प्रदान करके प्रोत्साहित किया गया था।
- शहरी प्रशासन के लिए मुख्य उपाय:
 - ● गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय हितधारकों के रूप में उनकी भागीदारी महत्वपूर्ण है।
 - ● सामाजिक जवाबदेही उपकरणों के प्रभावी होने के लिए गरीबों के हितों का समावेश महत्वपूर्ण है।
 - ● चर्चा गरीबों की तात्कालिक जरूरतों पर केंद्रित होनी चाहिए और वार्ड स्तर के प्रतिभागियों की क्षमता निर्माण आवश्यक है।
 - ● एक स्थायी प्रक्रिया के लिए भागीदारों के बीच साझा हित और जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है।
- इस प्रकार, शहरी विकास में सामुदायिक भागीदारी सिद्धांतों को सरकारों द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए लेकिन समवर्ती जिम्मेदारियाँ, भागीदारों की भूमिका परिभाषाएँ और संस्थागतकरण जैसी चुनौतियाँ हैं।



गवर्नेंस फाउंडेशन

पता वी/18, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, लोअर ग्राउंड फ्लोर, नई दिल्ली - 110016

ईमेल पता - governancef@gmail.com

संपर्क करें - +91-8447625205

वेबसाइट - www.governancefoundation.org.in